INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 12 | ISSUE - 3 | APRIL - 2022

नागपुर जिले में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास में राष्ट्रीयकृत बैंकों के योगदान का अध्ययन

प्रिती गणेशप्रसाद साहू[१] , डॉ. सदानंद एस. धकीत[२]
[१]शोध छात्रा
[२]शोध मार्गदर्शक, श्री. बिंझाणी नगर महाविद्यालय, नागपूर.

साराशं

नागपुर जिला औद्योगिक दृष्टि से 'सी' श्रेणी का पिछडा जिला होने से औद्योगिक विकास की अपार सम्भावनाएँ है। जिले का औद्योगिक विकास लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से ही सम्भव है क्योंकि यहाँ ७२.२ प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है तथा ६९.४ प्रतिशत कामकाजी व्यक्ति कृषक या खेतिहर मजदूर के रूप में कृषि कार्य करते है। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी, अर्द्ध बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना रोजगार एवं पूंजी निर्माण के लिए बैंकों का विकास भी अपरिहार्य बन जाता है। विषय का चयन इसी अध्ययन के औचित्य को दर्शाता हैं।

प्रस्तुत शोध कार्य में १४ तहसीलों में ७०० लघु तथा कुटीर उद्यमियों का सर्वेक्षण किया गया। इन तहसीलों में प्रत्येक तहसील से ५० उद्यमी तथा कुल २८ राष्ट्रीयकृत बैंक से स्वतंत्र साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से जानकारी संकलीत की गई।

परिचय

भारतीय उद्योगों का इतिहास प्राचीन एवं विश्व प्रसिद्ध रहा है। यहाँ के लोग कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में निपूण होते थे। भारत का वस्त्र उद्योग भी विश्व प्रसिद्ध था। मुगलकाल के समय भारत में आये प्रसिद्ध पर्यटक टॅवर्नियर ने भारतीय उद्योगों के उत्कर्ष के सम्बन्ध में कहा था कि ''भारत में बनी हुई वस्तुएँ इतनी हल्की एवं सुन्दर होती है कि हाथ में होते हुए भी यह आभास नहीं होता है कि वे हाथ में है।'' शाही औद्योगिक आयोग ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि ''जिस समय आधुनिक उद्योगों कि जन्मभूमि पश्चिमी यूरोप में असभ्य जातियों का निवास था. उस समय भी भारत अपने शासकों की सम्पत्ति और शिल्पियों के उत्कृष्ट कला के लिए प्रसिद्ध था।'' भारतीय उद्योगों में जवाहरात, पीतल, तांबा एवं लकडी की कलात्मक वस्तुएँ विश्व विख्यात थी। इससे स्पष्ट है कि भारतीय औद्योगिक विकास में लघु एवं कुटीर उद्योगों की बाहुल्यता थी।

वित्त किसी भी व्यवसाय का प्राण होता है, बिना वित्त के कोई भी उपक्रम अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है। औद्योगिक वित्त की अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन आवश्यकता की पूर्ति में बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान होता हैं। बैंकों द्वारा प्रदत्त वित्त को आधुनिक वित्त प्रणाली की आधारशीला कहा गया है। जर्मनी, इंग्लैण्ड, जापान इत्यादी देशों के औद्योगिक विकास में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जर्मनी के औद्योगिक विकास में सम्पूर्ण श्रेय वहाँ की बैंकों की व्यवस्था को ही जाता है। भारत में भी मार्च, १९५१ में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदत्त कुल वित्तीय सहायता का ३३.५ प्रतिशत भाग उद्योगों में दिया गया. जो बढकर सन् १९६८ में ६०.६ प्रतिशत हो गया। वर्ष १९६९ में व्यावसायिक बैंकों द्वारा वितरित किए गय ऋणों में से लघु उद्योगों में ऋण का प्रतिशत ८.३ था जो वर्ष २००१ में बढकर १४.६ प्रतिशत हो गया। नई औद्योगिक नीति १९९१ की घोषणा के

पश्चात् बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को प्रदान किए जाने वाली वित्तीय कार्यभार में और अधिक वृद्धि की गई है। इस दृष्टि से लघु एवं कुटीर उद्योगों को अधिक वित्तीय सुविधाएँ प्रदान कर औद्योगिक विकास को बढाने के प्रयास किए जा रहे है।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैंको की धारणा में परिवर्तन आया और उन्होंने ग्राहकों के सामने नई–नई योजनाएँ प्रस्तुत की। बैंकों के लिए प्राथमिक क्षेत्रो का निर्धारण हुआ जिसके तहत् संख्यात्मक लक्ष्य निर्धारित किए गए। विभिन्न वर्गो और क्षेत्रों के लिए ऋण योजनाएँ तैयार की गई और कार्य योजनाओं के माध्यम से उन्हें क्रियान्वित किया गया। इसके साथ की वाणिज्य बैंकों ने ग्रामीण निर्धनों के विकास हेतु कृषक वर्ग को, लघु एवं कुटीर उद्यमियों, छोटे व्यापारियों तथा अन्य सेवा क्षेत्र के विकास के लिए काफी मात्रा में ऋण सहायत प्रदान की परन्तु इस सम्बन्ध में रही मायने में विपणन सेवाओं को विकसित नही किया जिसके अभाव में उपलब्ध कराई गई सहायता का अपेक्षित प्रभाव नहीं रहा।

सन् १९९१ की औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात् महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी प्रदेश में उद्योगों की स्थापना में उदार नीति अपनाई गई है। महाराष्ट्र शासन द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति में आर्थिक दृष्टि से पिछडे हुए क्षेत्रों के औद्योगिक विकास पर विशेष बल दिया गया है। महाराष्ट्र की उपराजधानी होते हुए भी नागपुर जिला मुंबई, पुणे औरंगाबाद आदी जिलों की तुलना में औद्योगिक दृष्टि से पिछडा हुआ है।

उपरोक्त मुद्दों को ध्यान मे रखते हुए नागपुर जिले में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास में राष्ट्रीयकृत बैंको के योगदान का अध्ययन इस शिर्षक के अंतर्गत शोध कार्य करने का प्रयास किया गया है।

तालिका क्र. १: ऋण सेवा में सुलभता लाने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योजकों के सुझाव

ऋण सेवा में सुलभता लाने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योजकों के सुझाव	संख्या	प्रतिशत
ब्याजदर कम करना चाहिए	४३१	६१.६
ऋण की किश्त की अवधि बढाई जानी चाहिए	२१९	३१.३
बँकद्वारा योग्य मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए	४१	५.९
अन्य.....	९	१.३
कुल	**७००**	**१००.०**
Chi –square	df	Sig.
६४५.६२३	**३**	**०.०००**

तालिका क्र. १ में ऋण सेवा में सुलभता लाने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योजकों के सुझाव के विषय में जानकारी दर्शाई गई है। प्राप्त जानकारी दर्शाती है की ६१.६ प्रतिशत उद्योजकों के अनुसार ऋण सेवा में सुलभता लाने के लिए ब्याजदर कम करना चाहिए। जबकि क्रमश: ३१.३, ५.९ तथा १.३ प्रतिशत उद्योजकों के अनुसार ऋण सेवा में सुलभता लाने के लिए ऋण की किश्त की अवधि बढाई जानी चाहिए, बँकद्वारा योग्य मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए तथा अन्य प्रयास किए जाने चाहिए। ऋण सेवा में सुलभता लाने के लिए दिए सुझावों के आधार पर की गई तुलना उनके बीच लक्षणीय (Chi-Square 645.623, df=3, $p<0.05$) अंतर दर्शाती है। प्रस्तुत संशोधन कार्य में प्राप्त जानकारी से यह निष्कर्ष निकाला जाता है की, ऋण सेवा में सुलभता लाने के लिए ब्याजदर कम करना चाहिए ऐसा सुझाव देने वाले लघु एवं कुटीर उद्योजकों की संख्या अन्य उद्योजकों की तुलना में अधिक है।

तालिका क्र. २: राष्ट्रीयकृत बँकों की ऋण सेवा की वजह से ग्रामीण भाग के किस क्षेत्र का ज्यादा विकास हुआ है इस विषय में लघु एवं कुटीर उद्योजकों की प्रतिक्रिया

राष्ट्रीयकृत बँकों की ऋण सेवा की वजह से ग्रामीण भाग के किस क्षेत्र का ज्यादा विकास हुआ है इस विषय में लघु एवं कुटीर उद्योजकों की प्रतिक्रिया	संख्या	प्रतिशत
कृषी	२५१	३५.९
अन्य व्यवसाय	१४८	२१.१
उद्योगधंदे	२०१	२८.७

अन्य	१००	१४.३
कुल	**७००**	**१००.०**
Chi –square	df	Sig.
७३.१७७	३	०.०००

तालिका क्र. २ में राष्ट्रीयकृत बँकों की ऋण सेवा की वजह से ग्रामीण भाग के किस क्षेत्र का ज्यादा विकास हुआ है इस विषय में जानकारी दर्शाई गई है। प्राप्त जानकारी दर्शाती है की ३५.९ प्रतिशत उद्योजकों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बँकों की ऋण सेवा की वजह से ग्रामीण भाग के कृषी क्षेत्र का विकास हुआ है। जबकि क्रमश: २१.१, २८.७ तथा १४.३ प्रतिशत उद्योजकों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बँकों की ऋण सेवा की वजह से ग्रामीण भाग के अन्य व्यवसाय, उद्योगधंदे तथा अन्य क्षेत्रों का विकास हुआ है। राष्ट्रीयकृत बँकों की ऋण सेवा की वजह से ग्रामीण भाग के किस क्षेत्र का ज्यादा विकास हुआ है इस आधार पर की गई तुलना उनके बीच लक्षणीय (Chi-Square 73.177, df=3, p<0.05) अंतर दर्शाती है। प्रस्तुत संशोधन कार्य में प्राप्त जानकारी से यह निष्कर्ष निकाला जाता है की, राष्ट्रीयकृत बँकों की ऋण सेवा की वजह से ग्रामीण भाग के कृषी क्षेत्र का विकास हुआ है इससे सहमती दर्शानेवाले लघु एवं कुटीर उद्योजकों की संख्या अन्य उद्योजकों की तुलना में अधिक है।

तालिका क्र. ३: ऋण की चुकौती राशी का भुगतान नियमित रूप से करने के विषय में लघु एवं कुटीर उद्योजकों की प्रतिक्रिया

ऋण की चुकौती राशी का भुगतान नियमित रूप से करने के विषय में लघु एवं कुटीर उद्योजकों की प्रतिक्रिया	**संख्या**	**प्रतिशत**
हाँ	५७३	८१.९
नही	१२७	१८.१
कुल	**७००**	**१००.०**
Chi –square	df	Sig.
७३.१७७	३	०.०००

तालिका क्र. ३ में ऋण की चुकौती राशी का भुगतान नियमित रूप से करने के विषय में जानकारी दर्शाई गई है। प्राप्त जानकारी दर्शाती है की ८१.९ प्रतिशत उद्योजकों के अनुसार ऋण की चुकौती राशी का भुगतान नियमित रूप से करना चाहिए। जबकि १८.१ प्रतिशत उद्योजकों के अनुसार ऋण की चुकौती राशी का भुगतान नियमित रूप से नहीं करना चाहिए। ऋण की चुकौती राशी का भुगतान नियमित रूप से करना चाहिए इस आधार पर की गई तुलना उनके बीच लक्षणीय (Chi-Square 73.177, df=3, p<0.05) अंतर दर्शाती है। प्रस्तुत संशोधन कार्य में प्राप्त जानकारी से यह निष्कर्ष निकाला जाता है की, ऋण की चुकौती राशी का भुगतान नियमित रूप से करना चाहिए इससे सहमती दर्शानेवाले लघु एवं कुटीर उद्योजकों की संख्या अन्य उद्योजकों की तुलना में अधिक है।

तालिका क्र. ४: बँकींग व्यवहार संभालने हेतू प्रशिक्षण प्राप्त करने के विषय में लघु एवं कुटीर उद्योजकों की प्रतिक्रिया

बँकींग व्यवहार संभालने हेतू प्रशिक्षण प्राप्त करने	**संख्या**	**प्रतिशत**
हाँ	१८२	२६.०
नही	५१८	७४.०
कुल	**७००**	**१००.०**
Chi –square	df	Sig.
१६१.२८	१	०.०००

तालिका क्र. ४ में बँकींग व्यवहार संभालने हेतू प्रशिक्षण प्राप्त करने के विषय में जानकारी दर्शाई गई है। प्राप्त जानकारी दर्शाती है की २६.० प्रतिशत उद्योजकों ने बँकींग व्यवहार संभालने हेतू प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जबकि ७४.० प्रतिशत उद्योजकों ने बँकींग व्यवहार संभालने हेतू प्रशिक्षण प्राप्त नही किया है। बँकींग व्यवहार संभालने हेतू प्रशिक्षण प्राप्त करने के आधार पर की गई तुलना उनके बीच लक्षणीय (Chi-Square 161.28, df=1, p<0.05) अंतर दर्शाती है। प्रस्तुत संशोधन कार्य में प्राप्त

जानकारी से यह निष्कर्ष निकाला जाता है की, बँकींग व्यवहार संभालने हेतू प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लघु एवं कुटीर उद्योजकों की संख्या अन्य उद्योजकों की तुलना में अधिक है।

निष्कर्ष

- ऋण सेवा में सुलभता लाने के लिए ब्याजदर कम करना चाहिए ऐसा सुझाव देने वाले लघु एवं कुटीर उद्योजकों की संख्या अन्य उद्योजकों की तुलना में अधिक है।
- ऋण की चुकौती राशी का भुगतान नियमित रूप से करना चाहिए इससे सहमती दर्शानेवाले लघु एवं कुटीर उद्योजकों की संख्या अन्य उद्योजकों की तुलना में अधिक है।
- बँकींग व्यवहार संभालने हेतू प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लघु एवं कुटीर उद्योजकों की संख्या अन्य उद्योजकों की तुलना में अधिक है।
- ग्रामीण उद्यमीयों के आर्थिक स्थिती में सुधार लाने हेतु बँकों द्वारा कुटीर उद्योगों को बढावा दिया जा रहा है यह मत रखनेवाले लघु एवं कुटीर उद्योजकों की संख्या अन्य उद्योजकों की तुलना में अधिक है।

सदर्भ

- उत्तर प्रदेश (१९७६), भारत बुक सेन्टर, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, पृ. २८४.
- 'प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारूप (१९५१).
- रिपोर्ट ऑन स्माल इण्डस्ट्रीज इन इण्डिया बाई दि इण्टरनेशनल प्लानिंग टीम, (१९५४).
- इण्डिया, (१९७६), पृष्ठ २८०–२८३.
- प्रतियोगिता साहित्य सिरीज–सामान्य अध्ययन (२००९), पृष्ठ एफ–९६
- प्रतियोगिता साहित्य सिरीज–सामान्य अध्ययन (२००९), पृष्ठ एफ–९७.
- लघु उद्यम मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, २००६–०७, पृष्ठ–९.
- लघु उद्यम मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, २००६–०७, पृष्ठ–१०.
- Mahbub-UI-Haq: "Employment and Income Distribution in 1970s: A New Perspective", Pakistan Economic and Social Review, June-December, 1971, p-6.
- Charles P. Kindleberger and Bruce Herrick, Economic Development (New York, 1977), p.1.
- Dudle Seers, "The Meaning of Development" Eleventh World Conference of the Society for International Development (New Delhi), 1969, p.3.
- Regnar-Nurkse, Op.cit., p-11.
- Singh, P. N. (1975). Role of development banks in a planned economy. Vikas Publishing House.
- Singh, P. N. (1975). Role of development banks in a planned economy. Vikas Publishing House.